metro cities at and Telecom Circles and the information in respesct of Basic Telephone service is given in Annexure. (*See* Appendix 181 Annexure No. 25)

Change in equity structure/partners for basic and cellular operators

777. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether any proposal has been received by the DoT for change in equity structure/partners for basic and cellular operators including LCI holders;

(b) if so, the details of all such proposal received including the names of the original promoters/shareholders as well as the names of new promoters/ shareholders; and

(c) the decision taken by the DoT on all such proposals?

THE MINISTER OF COMMUNICATION (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Yes Sir.

(b) and (c) As per the details given in the Annexure. (*See Appendix 181 Annexure No. 26.*

Post/Sub-Post Offices in Rural Areas of Gujarat

778. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of COMMUNICATION be pleased to state:

(a) the number of Post/Sub-Post Offices functioning in rural areas of Gujarat at present;

(b) the number of villages in the State where there is no postal facilities available so far;

(c) whether it is a fact that a number of representations for opening of Post Offices/Sub-Post Offices have been received by Governments; and

(d) if so, the action taken so far and by when Government propose to provide postal facilities there?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) The number of Post/Sub-Post Offices functioning in rural areas of Gujarat at present, is 8142.

(b) The number of villages in the State where there is no post office, is 9922. However, postal facilities are being made available to such villages from nearby post offices.

(c) Yes, Sir.

(d) The representations for opening post offices received from various quarters are examined and post offices are sanctioned on norm based justification subject to availability of resources and Plan targets. Under the Annual Plan 1997-98, a target of opening 2 Departmental Sub-Post Offices and 25 Extra Departmental Branch Post Offices has been fixed for Gujarat Circle.

नए डाकघर खोलने के लिए जनप्रतिनिधियों और विभाग से अभ्यावेदन

779. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जनप्रतिनिधियों एवं विभाग ने वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान नए डाकघर खोलने के लिए उनके मंत्रालय/विभाग को अनेक प्रतिवेदन अनुमोदनार्थ भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां नए डाकघर खोलने संबंधी प्रस्तावों पर विभाग विचार कर रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश परिमंडल, शिमला के पोस्टमास्टर जनरल ने हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला के सुल्तान पुर में एक डाकघर खोलने के लिए अपनी अनुशंसा सहित एक प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) नए डाकघर खोलने के लिए जन प्रतिनिधियों और विभाग द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदनों के ब्यौरों से

संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जिन स्थानों पर डाकघर खोलने के प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन हैं, उनका राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अपर सुलतानपुर में विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था क्योंकि इसमें विभागीय पदों का सृजन शामिल है। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने पर मंजूर किए जाते हैं बशर्ते कि संसाधन और योजना लक्ष्य उपलब्ध रहें।

(देखिये परिशिष्ट 181 अनुपत्र सं॰ 27)

Agreement with French Telephone Firm

780. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a French Telephone Firm is likely to setp up operation in India to market wireless, wireline etc.

(b) if so, the terms and conditions in this regard;

(c) whether any agreement has been made with this firm; and

(d) if so, the details of the agreement?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) to (d) A Financial Protocol between the Govt. of the French Republic and the Govt. of India was signed on 1.12.94. Amongest various projects covered in the Protocol, a pilot project for urban mobile telephones was to be funded through a 2 million FF grant-I million included in the Protocol and I million FF form the French Company, M/S. DASSAULT.

However, the pilot project for urban mobile a telephones could not take off under the Indo-French Aid.

DOT has placed an order on M/S. DASSAULT, France, for supply of two systems of 1000 subscribers capacity each of CT-2 Technology for Wireless in Local Loop for field trial at Calcutta and Vajayawada at a cost of FF 84,63,320. Field trial of the system is under progress.

हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन का न लगाया जाना

781. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार परिमंडल, शिमला के मुख्य महाप्रबंधक, ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 1997 के ज्ञापन सं॰ कामश्र्थल/11-6/97/13 के माध्यम से प्रश्नकर्ता की अनुशंसा पर हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर एक टेलीफोन लगाने के लिए स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो आज तक इस टेलीफोन के न लगने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए जिम्मेवार दोषी व्यक्तियों के नाम क्या है तथा दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यह टेलीफोन कब तक लगा दिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोन कनेक्शन के आबंटिती द्वारा संबंधित प्राधिकारी को अपना पंजीकरण विवरण अभी देना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आबंटिती द्वारा उपर्युक्त (ख) पर उल्लिखित आवश्यक विवरण जब उपलब्ध करवा दिए जाते हैं बशर्ते कि अन्य औपचारिकताएं और तकनीकी व्यवहार्यता पूरी होती हो।